अनुलग्नक

अक्टूबर, 2023 माह के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख नीतिगत निर्णयों/गतिविधियों पर मासिक सारांश

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,884 शहरों / कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ + + और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड़, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वाटर + रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मानचित्र पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से देखा जा सकता हैं।

iii. स्वच्छता ऐप महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा हैं, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें ऐप में दर्ज करा सकते हैं, ताकि नगर निगम द्वारा उनका समाधान किया जा सके।स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. एक तारीख, एक घंटा एक साथ

अक्टूबर 1, सुबह 10 बजे, स्वच्छ भारत की यात्रा एक नया इतिहास लिखे जाने की गवाह बनी। देश भर में करोड़ों नागरिक एक विशाल स्वच्छता अभियान में स्वैच्छिक श्रमदान करने के लिए आगे आए । **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी** श्रमदान हेतु लोकप्रिय फिटनेस प्रभावकार अंकित बैयनपुरिया से जुड़े ।

नागरिकों के स्वामित्व और नेतृत्व में, इस मेगा स्वच्छता अभियान में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, गांवों और शहरों से भागीदारी देखी गई है। औसत संख्या यह इंगित करती है कि कुल मिलाकर 9 लाख से अधिक साइटों पर लगभग 8.75 करोड़ लोगों की भागीदारी दर्ज हुई है। सड़कों, राजमार्गों और टोल प्लाजा, रेलवे ट्रैक और स्टेशनों, टोल प्लाजा, स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, विरासत और पर्यटक स्थानों, आवासीय कॉलोनियों, जल निकायों, धार्मिक स्थलों, स्लम, बाजार क्षेत्रों, हवाई अड्डों और आसपास के क्षेत्रों, चिड़ियाघर और वन्यजीव क्षेत्र, गौशालाएं आदि में सफाई अभियान चलाया गया।

हजारों नागरिक समाज संगठनों और जनता के साथ कई राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व भी इसमें शामिल हुए । जवानों , नागरिकों, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईके स्वयंसेवकों, एसएचजी, गैर सरकारी संगठनों, आरडब्ल्यूए, बाजार संघों, उद्योग निकायों, आस्था नेताओं, मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, यूट्यूबर्स , कलाकारों आदि ने इस मेगा पहल के लिए मिलकर काम किया।

सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन ने 1000 सार्वजनिक शौचालयों को साफ करने के लिए लगभग 50,000 नागरिकों का नेतृत्व किया। माता अमृतानंदमयी के आश्रमों के नेटवर्क और अमृता संस्थानों के समूह ने निवासियों और भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सफाई की। ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने केंद्र के पास के ग्रामीण इलाकों में सड़कों, कॉलोनियों, शौचालयों की सफाई की। बाबा रामदेव योगपीठ ने 30,000 नागरिकों के साथ पार्कों, आवासीय क्षेत्रों और राजमार्गों सहित 1000 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस्कॉन के सैकड़ों स्वयंसेवक सड़कों की सफाई के लिए एकजुट हुए। क्रेडाई, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, ब्रिटानिया, बजाज, आदित्य बिड़ला, अमेज़ॅन आदि ने भी भाग लिया। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इलैयाराजा, जैसी हस्तियां भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य और कई अन्य लोग सार्वजनिक लामबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल हुए। रिकी केज, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, राजकुमार राव जैसे कई लोग ज़मीनी कार्रवाई में भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड, गुरुद्वारा स्वयंसेवक, रोटरी क्लब, आगा खान फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन आदि संगठनों ने भी भागीदारी की। बीएमजीएफ, यूएसएआईडी, यूनिसेफ, जीआईजेड जैसे सेक्टर भागीदार भी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री भी विभिन्न स्थलों पर श्रमदान में शामिल हुए। 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के परिणामस्वरूप एक ही समय में लाखों स्थलों पर श्रमदान स्वयंसेवकों के लिए सहज सुविधा उपलब्ध हुई। जब समर्पित स्वयंसेवकों के छोटे समूह अपने चुने हुए स्थलों को साफ़ करने में सक्षम हुए तो उनके द्वारा एक उपलब्धि की अनुभूति की गई। पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की अधिक थी। इस अतुल्य समय में लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने कचरा संग्रहण, परिवहन, सुरक्षित निपटान आदि के लिए पहल की। प्रत्येक श्रमदान शून्य अपशिष्ट और प्लास्टिक मुक्त के सिद्धांतों को अपनाकर साइट का आयोजन किया गया था।

24 सितंबर, 2023 को 105वें मन की बात के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कार्रवाई के आह्वान के बाद मिशन ने तेजी से एक सक्षम प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे

का निर्माण किया, जहां लोग पंजीकरण कर सकते थे, पहचान कर सकते थे और श्रमदान के लिए अपनी पसंदीदा साइट का चयन कर सकते थे । एक मजबूत बैकएंड बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया गया, जिससे शहर के अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, कॉर्पोरेट निकायों आदि को पंजीकरण करने की अनुमति मिली। कूड़ा-कचरे के प्रति संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे जनता को अपनी पसंद की साइटों को चुनने और उनमें शामिल होने में मदद मिली। श्रमदान के दिन वे अपनी तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं और भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

II. स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम)

i. 1,70,983 करोड़ रुपये की 7,939 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,13,837 करोड़ रुपये की 6,187 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

ii. अक्टूबर माह के दौरान 2,798 करोड़ रुपये की 90 अतिरिक्त परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

iii. स्मार्ट शहरों में लेबलिंग कार्यनीति का कार्यान्वयन

अब तक, 40 स्मार्ट शहरों ने लेबलिंग कार्यनीति के हिस्से के रूप में, विभिन्न परियोजना स्थलों पर साइनेज , स्टैंडीज़ आदि लागू किए हैं। साइनेज , पोस्ट और स्टैंडीज़ की स्थापना ने मिशन परियोजनाओं के बारे में सूचित संवाद को सक्षम किया है, जिससे अतीत पर प्रतिबिंब और भविष्य के लिए योजना बनाई जा सके।

iv. स्ट्रीट और पब्लिक स्पेसेस वर्कशॉप

26 से 27 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में दो दिवसीय 'सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय कार्यशाला' का आयोजन किया गया।

vii. मिशन में उल्लेखनीय प्रगति

viii. शहरों को साक्ष्य-आधारित स्मार्ट गवर्नेंस में मदद करने के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) **100 स्मार्ट शहरों** में संचालित किए गए हैं।

- दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए **180 पीपीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं** और **28 परियोजनाएं लगभग 2,839 करोड़ रुपये** के निवेश के साथ प्रक्रियाधीन हैं।

- **1,107 जीवंत सार्वजनिक स्थान** (नदी/झील के किनारे, पार्क और खेल के मैदान और पर्यटन स्थल) **परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं** ।

- शहरों को अधिक जीवंत और सुस्थिर बनाने के लिए **1,209 डब्ल्यूएएसएच परियोजनाएं और 601 स्मार्ट ऊर्जा परियोजनाएं** पूरी की गई हैं।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. आज की तारीख में, 77,640 करोड़ रुपये की अनुमोदित कार्य योजना से अधिक 83,146 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अधिक राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 41,606 करोड़ रुपये की 5,091 परियोजनाओं के लिए कार्य पूरा किया जा चुका है और 41,298 करोड़ रुपये की 811 परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, लगभग 74,110 करोड़ रुपये का भौतिक कार्य पूर्ण/चल रही अमृत परियोजनाओं में किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 95% भौतिक कार्य पूरा किया जा चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई), सुधार प्रोत्साहन और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना' और 25 चयनित शहरों में 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) पर उप-योजनाओं के तहत 40,342 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अन्त्योदय योजना /राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर माह के दौरान 10,660 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया है; 4,131 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया; 6,940 व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने में सहायता की गई और 8,998 को ऋण दिया गया। एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को ऋण दिए गए ।

V. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. आरंभ से, मिशन ने 1.19 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 113.39 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिनमें से 77.50 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/ सुपुर्द किए जा चुके हैं।

ii. अक्टूबर माह,2023 के दौरान पीएमएवाई (यू) के तहत 498.49 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

VI. आवास

i. सभी राज्यों/*संघ राज्य क्षेत्रों* ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, नागालैंड को छोड़कर,जो नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 32 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (नियमित -27,अंतरिम -05) की स्थापना की । *लद्दाख , मेघालय और सिक्किम ने नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है जबकि प्राधिकरण की स्थापना अभी बाकी है।*

iii. 28 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों* ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित -24, अंतरिम - 04) की स्थापना की है *(अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख , मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।*

iv. 30 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों के* नियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटे संचालित कर दी हैं *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में चालू करने की प्रक्रिया चल रही है)।*

v. 26 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त कर दिए है और* 12 राज्यों/ *संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त नहीं किए है।*

vi. देशभर में 1,15,912 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 82,540 रियल एस्टेट एजेंटों ने रेरा के तहत पंजीकरण कराया है।

vii. पूरे देश में 1,15,808 शिकायतों का निपटान किया गया है, जिनमें से 1,412 शिकायतों का समाधान अक्टूबर माह, 2023 में किया गया। अक्टूबर माह, 2023 के दौरान 3,440 परियोजनाएं और 1,230 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत किए गए हैं । .

viii. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य पहले ही एमटीए के पहले के मसौदे के आधार पर किरायेदारी अधिनियमों को अधिसूचित कर दिया हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने किरायेदारी कानूनों को मॉडल किरायेदारी अधिनियम (एमटीए) के नवीनतम संस्करण के साथ संरेखित करें।असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एमटीए के नवीनतम संस्करण की तर्ज पर असम राज्य में अधिनियमित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को (i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन, 2023, (ii) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 और (ii) लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को भी मंजूरी दे दी है ।

Vii. पीएम पथ-विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)

i. पीएम पथ-विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) के तहत 92,72,574 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 75,84,032 स्वीकृतियां दी गई है और 70,82,013 संवितरित किए गए हैं।

ii. अक्टूबर माह, 2023 के दौरान मिशन के तहत कुल 18.754 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

Viii. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

i) माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने 4.10.2023 को कोटा, राजस्थान में युवा छात्रावास भवन का उद्घाटन किया।

ii) माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने एनआईटीटीटीआर, चेन्नई में डॉ. एस. राधा कृष्णन इंटरनेशनल हॉल ऑफ रेजिडेंस और अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया।

iii) 26.10.2023 को ईटानगर में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्वी हिमालय जीव-जंतु भंडार (ईएचएफआर) के निर्माण की आधारशिला रखी।

iv) बरखेरा बोंडर, भोपाल में एनएफएसयू के नए परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

v) सीपीडब्ल्यूडी ने 04.10.2023 से 06.10.2023 तक सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें" पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

vi) 25 से 27 अक्टूबर 2023 तक राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी, गाजियाबाद में सीपीडब्ल्यूडी में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग (बीआईएम) के लिए क्षमता निर्माण पर प्रथम व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया।